

एन०एस०नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

विषय: मै० ब्रोसिंल ग्लास वर्क्स लिमिटेड को तहसील रुड़की के ग्राम नल्हेड़ी देहविरान में कुल 11.78 एकड़ भूमि क्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून : दिनांक : १५ जनवरी, २००७

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-६२८३/भूमि व्यवस्था-भू०क० दिनांक १० नवम्बर, २००६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै० ब्रोसिंल ग्लास वर्क्स लिमिटेड को उत्तरांचल (उ०प्र० जर्मीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम नल्हेड़ी देहविरान में कुल 11.78 एकड़ भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :—

१— केता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

२— केता वैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

३— केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्यय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्यय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-१६७ के परिणाम लागू होंगे।

४— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूरवामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

- 5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6— प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 7— प्रस्तावित क्य की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रचलित नियमों/मानकों एवं उपलब्धियों के अन्तर्गत नियमानुसार भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 8— प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडी)–2005 के अनुरूप निर्माण होगा।
- 9— प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10— इकाई द्वारा क्य की जा रही भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु किया जायेगा।
- 11— प्रश्नगत उद्योग की स्थापना से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 12— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 2— तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलव्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य राजरव आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5— श्री पी०के०खैरुल्का, डायरेक्टर, मै० ब्रोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड, खन्ना कन्स्ट्रक्शन हाउस, 44 डॉ० आर०जी०थडानी मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400018
- 6— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुनील सिंह)
अनु सचिव।